क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 320, गुरुवार, 20 दिसम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

गुजरात : छह लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं का 625 करोड़ का बिजली बिल माफ

अहमदाबाद एजेंसी। गुजरात की विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रपए का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया। एकमुश्त समाधान योजना के तहत यह बकाया माफ किया गया है। गुजरात सरकार ने यह कदम उठाया है। गांधीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए गुजरात के बिजली मंत्री सौरभ पटेल ने कहा कि सरकार की इस योजना का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जिनके खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग केवल 500 रपए का भुगतान करके बिजली कनेक्शन वापस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं करने को लेकर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 6.20 लाख लोगों के बिजली कनेक्शन काटे हैं। इन बिजली बिलों की बकाया राशि करीब 625 करोड़ रपए है।

सज्जन कुमार ने कांग्रेस छोड़ी

नई दिल्ली एजेंसी। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार, लोकसभा के पूर्व सदस्य ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा है कि वह तत्काल प्रभाव से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। बाहरी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से तीन बार चुने गए सज्जन कुमार को पार्टी ने उनकी दंगों में सलिप्तता के आरोपों के मद्देनजर वर्ष 2009 से टिकट नहीं देकर दरकिनार करना शुरू कर दिया था। उच्च न्यायालय ने सोमवार को 84 के दंगों को ''मानवता के विरुद्ध अपराध' कहा था। कुमार ने हालांकि मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनके वकील ने कहा कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाने की प्रक्रिया में हैं। इस बीच, माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने सज्जन कुमार के बारे में बयान देने से इनकार कर दिया। संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि उनकी प्रेस वार्ता नरेंद्र मोदी और किसान ऋण मुद्दे पर है। कुमार के बारे में पूछे जाने पर राहुल ने कहा, मैंने दंगों पर अपना पक्ष बहुत ही स्पष्टता के साथ रख दिया है, यह प्रेस वार्ता किसानों के बारे में है।

गुजरात सरकार ने ग्रामीणों का 625 करोड़ का बिजली बिल किया माफ

अहमदाबाद। एजेंसी। गुजरात की विजय रुपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया। एकमुश्त समाधान योजना के तहत यह बकाया माफ किया गया है। राजकोट जिले की जसदन विधानसभा सीट पर 20 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले गुजरात सरकार की यह घोषणा सामने आई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के अनुरूप एक दिन पहले ही कृषि कर्ज माफी के ऐलान के एक दिन बाद गुजरात सरकार ने यह कदम उठाया है। गांधीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए गुजरात के बिजली मंत्री सौरभ पटेल ने कहा कि सरकार की इस योजना का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जिनके खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं।

नियम न बनने तक दवाओं की ऑनलाइन बिक्री नहीं : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फार्मेसियों द्वारा खुली बिक्री या डाक्टरों के सुझाव पर दी जाने वाली दवाओं की बिक्री पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि इस संबंध में नियम नहीं बन जाते। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वीके राव की पीठ ने कहा कि एक बार नियम प्रभाव में आ जाने दीजिए, आप दवाओं की बिक्री शुरू कर सकते हैं। समस्या यह है कि अभी इसके नियमन के कोई नियम नहीं हैं।'' पीठ यहां कुछ ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ऑनलाइन दवा बेचने वाली इन कंपनियों ने अदालत से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था।

जबलपुर में नर्मदा नदी के ऊपर उड़ते परिंदे और उन्हें दाना खिलाते श्रद्धालु।

सोशल मीडिया पर की सरकार की आलोचना, 1 साल के लिए हिरासत में पत्रकार

नई दिल्ली एजेंसी। भाजपा नीत केंद्र और राज्य सरकार की, सोशल मीडिया पर आलोचना करने वाले एक पत्रकार को स्थानीय अदालत ने एक साल हिरासत में रखने की सजा सुनाई है। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। इंफाल वेस्ट जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 दिसंबर को यह आदेश पारित किया। पीटीआई-भाषा को इस बयान की प्रति बुधवार को मिली।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के परामर्श बोर्ड ने 11 दिसंबर को अपनी बैठक में पत्रकार किशोरचंद वांगखेम के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की। बयान में बताया गया कि 13 दिसंबर को बोर्ड ने सिफारिश की कि वांगखेम को एनएसए के प्रावधानों के तहत हिरासत में लेने के पर्याप्त आधार हैं। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने एनएसए के तहत 12 महीने तक पत्रकार को हिरासत में रखने की परामर्श बोर्ड की अनुशंसाओं को स्वीकृति दे दी। इंफाल के 39 साल के पत्रकार को एनएसए के तहत 26 नवंबर को हिरासत में लिया गया। रानी झांसी की जयंती मनाने के लिए केंद्र और मणिपुर की भाजपा नीत सरकार की आलोचना करते हुए कई वीडियो कथित तौर पर अपलोड करने के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया।

अधिकारियों ने इससे पहले कहा था कि वांगखेम एक स्थानीय टीवी चैनल में काम करते हैं और अंग्रेजी और मेती में 19 नवंबर को अपलोड किए गए वीडियो उनके आधिकारिक कार्य से संबद्ध नहीं थे। वीडियो क्लिप में वांगखेम ने कथित तौर पर कहा था कि वह मणिपुर में झांसी की रानी की जयंती मनाए जाने से अचंभित एवं दुखी हैं क्योंकि उनके कार्यों का राज्य से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन केंद्र के कहने पर राज्य सरकार जयंती मना रही है। साथ ही उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को कथित तौर पर 'केंद्र की कठपुतली और 'हिंदुत्व की कठपुतली कहा था।

आगरा में बीटेक की छात्रा को अगवा कर किया गैंगरेप, विरोध करने पर पीटा

आगरा। उत्तर प्रदेश की ताजनगरी में इंजीनियरिंग छात्रा से गैंगरेप की वारदात से सनसनी फैल गई। थाना न्यू आगरा के पास भगवान टॉकीज चौराहे से छात्रा को अपहृत कर वारदात को अंजाम दिया गया। पोइया घाट के पास छात्रा लहूलुहान हाल में मिली। लेडी लॉयल अस्पताल में मेडिकल के बाद छात्रा को एसएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। सनसनीखेज वारदात की सूचना पर एसएसपी समेत पूरा अमला मौके पर पहुंच गया। पीड़िता के परिजनों से मिले। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। भगवान टॉकीज से किया अगवा: थाना क्षेत्र निवासी एक युवती आगरा के एक कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा है। वह कंप्यूटर का कोर्स भी कर रही है। मंगलवार शाम करीब 5.30 बजे स्कूटी से घर लौट रही थी। भगवान टॉकीज चौराहे के पास एक शोरूम के सामने से दो युवकों ने उसे अगवा कर लिया। एक युवक ने उसे धक्का देकर पीछे किया और खुद स्कूटी चलाकर ले गया। दोनों युवक उसे पोइया घाट रोड की ओर ले गए।

चार युवकों ने किया रेप, विरोध पर पीटा

दो अन्य युवक आ गए। चारों ने गैंगरेप किया। विरोध पर छात्रा के सिर पर डंडों से वार किए। इसके बाद आरोपी पीड़िता को प्रिल्यूड स्कूल के पीछे झाड़ियों में फेंक गए।

12 घंटे में दूसरी बड़ी घटना से पुलिस के हाथ-पांव फूले

इंजीनियरिंग छात्रा से गैंगरेप की वारदात से सनसनी फैल गई। 12 घंटे में दूसरी बड़ी घटना से आगरा पुलिस के हाथ-पैर फूल गए।

सिख दंगों पर बोले, किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस नेता को मिलेगी सजा

ऑनलाइन सेवाओं से करप्शन ऑफ: मोदी

मोदी ने किया मेट्रो व आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ
इन परियोजनाओं पर आएगी 33,000 करोड़ रपए की लागत
राफेल फैसले को लेकर भी कांग्रेस पर साधा निशाना

मुंबई एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को वृहन्न मुंबई क्षेत्र में दो मेट्रो रेल लाइन परियोजनाओं और एक बड़ी सस्ती आवास परियोजना का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर कुल 33,000 करोड़ रपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। मोदी ने आगामी आम चुनावों से कुछ माह पूर्व यहां आयोजित एक कार्यक्रम में ठाणो-भिवंडी-कल्याण (मेट्रो रेलमार्ग-पांच) और दहीसर-मीरा भयंदर (मेट्रो रेलमार्ग-नौ) का शिलान्यास किया। इनकी संयुक्त लागत करीब 15,000 करोड़ रपए आंकी गई है। इसके अलावा उन्होंने नवी मुंबई शहरी नियोजन प्राधिकरण और राज्य सरकार के सिडको (नगर एवं औद्योगिक विकास निगम) की आवासीय योजना का भी शुभारंभ किया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18,000 करोड़ रपए की लागत से 89,771 कम दाम की आवास इकाइयों का निर्माण किया जाना है। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी थे।

ठाणो-भिवंडी-कल्याण मेट्रो रेलमार्ग-पांच की अनुमानित लागत 8,416 करोड़ रपए है। 24.9 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 17 स्टेशन होंगे। पूरी पग्राली छह कोच की मेट्रो रेल के मुताबिक तैयार की जाएगी। वर्ष 2021 तक इस मार्ग से 2.29 लाख लोगों के रोजाना सफर करने की उम्मीद है। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जीवन प्रमाण पत्र तक की सुविधाएं ऑन लाइन हैं। बिजली-पानी के बिल से लेकर, अस्पतालों में अप्वाइंटमेंट, बैंकों का लेनदेन, पेंशन, प्राविडेंट फंड, एडमिशन, रिजग्रेशन, करीब-करीब हर सुविधा को ऑन लाइन किया गया है ताकि कतारें न लगें और करप्शन की गुंजाइश कम हो। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणो में एक कार्यक्रम में कही।

मोदी ने कहा, पुणो इंजीनियरिंग और बिजनेस का सेंटर है। यही न्यू इंडिया की पहचान होने वाली है। स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से भारत भविष्य की तकनीकी का एक बड़ा सेंटर बनता जा रहा है।

स्टार्टअप के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए हमारे पास आवश्यक इंफ्रास्टक्चर तैयार है और हजारों युवा साथियों की एक

इनोवेटिव माइंड्स की फौज भी हमारे पास तैयार है। इसके इतर मोदी ने मुंबई में ''रिपब्लिक समिट' में 1984 सिख विरोधी दंगों में दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसले को रेखांकित करते हुए कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस नेता को मामले में दोषी ठहराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, चार साल पहले, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता को सजा मिलेगी और उन्हें (पीड़ितों को) इंसाफ मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने और उन्हें ताउम्र कैद की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद मोदी ने यह बयान दिया है। अदालत ने कल अपने आदेश में कहा था कि ये दंगे मानवता के खिलाफ अपराध थे और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद से उन लोगों द्वारा किए गए जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस तय से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरोपियों को सजा देने में तीन दशक लग गए लेकिन पीड़ितों को यह आश्वासन देना आवश्यक है कि अदालत के समक्ष पेश होने वाली चुनौतियों के बावजूद सत्य की जीत होती है और अंतत: न्याय मिलता है।मोदी ने राफेल सौदे पर उच्चतम न्यायालय के हाल ही में सुनाए फैसले को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा।

मोदी ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है जब भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों को लेकर देश की शीर्ष अदालत का रुख किया गया। जहां उन्हें स्पष्ट फैसला मिला कि जो भी काम हुआ (राफेल सौदे में.) वह पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ किया गया। उन्होंने कहा, चार साल पहले (जब कांग्रेस सत्ता में थी) किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने कहा, हमारी एक मानसिकता है जिसमें हम सरकार के खिलाफ अधिक भ्रष्टाचार के आरोपों में विास करते हैं। चाहे वह कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोप हों, मानसिकता एक ही बनी रहेगी।

जेटली के घर घुसा युवक, पूछताछ के बाद रिहा

नई दिल्ली एजेंसी। दक्षिणी दिल्ली के पॉश कैलाश कालोनी में केंद्रीय वित्त मंत्री के आवास में सोमवार रात एक युवक जबरन घुस गया। हालांकि सिक्योरिटी रूम में घुसे युवक को वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया। इस बीच युवक के वित्त मंत्री के घर में घुसने की खबर मिलते ही पुलिस हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस के अलावा अन्य कई जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं और एजेंसियों ने हिरासत में लिए गए युवक से गहन पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा पीटे जाने के बाद वह जान बचाने के लिए कैलाश कालोनी के एक मकान में घुस गया। उसे यह भी नहीं पता था कि यह किसका मकान है। हालांकि गहन पूछताछ के बाद आरोपी युवक को देर रात छोड़ दिया गया।पुलिस के अनुसार कैलाश कालोनी के एन-ब्लॉक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का आवास है। इस बीच सोमवार रात करीब नौ बजे वहां गणोश नामक युवक चिल्लाता हुआ मंत्री आवास के सिक्योरिटी रूम में घुस गया। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे काबू किया। बाद में मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह मूलरूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और पास के एक गेस्ट हाउस में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। सोमवार रात को जब वह घर वापस लौट रहा था। इस बीच वित्त मंत्री के घर के पास तीन-चार लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए वह उनके घर में घुस गया। गणोश ने बताया कि उसे नहीं पता था कि जिस घर में वह घुस रहा है वह वित्त मंत्री का है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। जिला पुलिस उपायुक्त विजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

बुलंदशहर हिंसा में दो और गोकशी के तीन आरोपी गिरफ्तार, इंस्पेक्टर के हत्यारे अभी भी फरार

बुलंदशहर। बुलंदशहर हिंसा में एसटीएफ ने वीडियो फुटेज से प्रकाश में आए दो आरोपी सचिन कोबरा और जोनी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा, पुलिस ने महाव में गोकशी के तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर, हिंसा की न्यायिक जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे यति नरसिंहानंद सरस्वती ने खून से सीएम को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वहीं, बुलंदशहर के चार विधायकों की मुख्यमंत्री से मुलाकात में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंसा में कोई भी बेकसूर जेल नहीं जाएगा। बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज समेत अभी 19 नामजद और 47 अज्ञात फरार चल रहे हैं। एसटीएफ क्राइम ब्रांच और पुलिस की 15 टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश डाल रही हैं। तीन दिसंबर को स्याना में गोकशी पर हुई हिंसा में गोली लगने से इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और युवक सुमित की मौत हो गई थी। एसआई सुभाष चन्द ने 27 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें मृतक सुमित भी नामजद था और मुख्य आरोपी बजरंग दल का जिला संयोजक योगेश राज है। अभी तक हिंसा मामले में 18 आरोपी जेल में बंद हैं।

अखिलेश यादव के बयान से लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लग सकता है झटका!

नई दिल्ली एजेंसी। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर बन रही विपक्षी एकता पर एक बार फिर ग्रहण लगता दिख रहा है। सपा मुखिया ने डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन के बयान पर अपनी सहमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि स्टालिन की राय पर गठबंधन के सभी सदस्य एकमत हों।

स्टालिन ने 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित किया है। इसके बाद से विपक्षी दलों के सुर बदल गए हैं। अब अखिलेश यादव भी इससे सहमत नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब बीजेपी से नाराज है।

इसी कारण कांग्रेस को तीन राज्यों में सफलता मिली है। अभी महागठबंधन का खाका तैयार किया जाना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, ममता बनर्जी और शरद पवार ने गठबंधन बनाने के लिए सभी नेताओं को एक साथ लाने का प्रयास किया था। इस प्रयास में अगर कोई अपनी राय दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि गठबंधन की राय समान हो।

प्रधानमंत्री पद के नाम पर किसी का भी नाम गठबंधन के सभी नेता तय करें तो बेहतर है। दरअसल, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया है। कयास लगाया जा रहा है कि शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के शपथ ग्रहण समारोह में मायावती, अखिलेश और ममता नहीं पहुंचे। इसके बाद अखिलेश का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ साबित करता है।

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस तरह का विचार दे रहा है तो जरूरी नहीं कि यह गठबंधन की राय हो।

अखिलेश यादव ने यह बात मंगलवार को लखनऊ में पत्रकारों के सवाल पर कही। उनसे पूछा गया कि डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने

आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित किया है। इसके बाद से विपक्षी दलों के सुर बदल गए हैं। अब अखिलेश यादव भी इससे सहमत नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब बीजेपी से नाराज है। इसी कारण कांग्रेस को तीन राज्यों में सफलता मिली है। अभी महागठबंधन का खाका तैयार किया जाना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, ममता बनर्जी और शरद पवार ने गठबंधन बनाने के लिए सभी नेताओं को एक साथ लाने का प्रयास किया था।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बताया है।

संपादकीय

ठंड की दस्तक

राजधानी दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है, और बीते सोमवार का दिन पिछले तीन सालों में सबसे ठंडा दिन रहा, लेकिन राफेल विमान सौदा के मसले को लेकर संसद के दोनों सदनों का माहौल काफी गरम रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं, और दोनों सदनों में यह मसला विशेषाधिकार हनन तक पहुंच गया है। राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने से मोदी सरकार उत्साहित है, तो दूसरी ओर कांग्रेस मानकर चल रही है कि राफेल सौदा बड़ा मुद्दा है, और तीन राज्यों के चुनावों में उसे मिली सफलता के पीछे इसकी बड़ी भूमिका रही है। हालांकि कांग्रेस के दावे में कितनी सचाई है, यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह राफेल सौदे को उछाल रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि आगामी लोक सभा चुनावों में कांग्रेस इस मुद्दे को जीवित रखना चाहती है। संसद के पिछले मानसून सत्र में भी राहुल ने राफेल सौदे में मोदी सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया था। इससे नाराज होकर भाजपा ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। कांग्रेस का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक (कैग) की जिस रिपोर्ट को अपने फैसले का आधार बनाया है, वह अस्तित्व में नहीं है और संसद की लोक लेखा समिति के साथ साझा नहीं की गई है। इसी आधार पर कांग्रेस सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगा रही है और इस मसले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग कर रही है। सरकार पूरी तरह से आास्त है कि राफेल सौदे में कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो उसे यह मांग मान लेने में देर नहीं करनी चाहिए। भारत की चुनावी राजनीति में कथित घोटालों की बड़ी भूमिका रहती आई है। घोटालों में शामिल आरोपियों के खिलाफ दोषसिद्ध भले न हो लेकिन चुनावों को कथित घोटाले गहरे तक प्रभावित करते हैं। बोफोर्स तोप घोटाला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। 1989 के लोक सभा चुनावों में कांग्रेस को हटाने में बोफोर्स की बड़ी भूमिका रही। यह और बात है कि आज तक इस मामले में किसी को सजा नहीं हो सकी है। दरअसल, आज के चुनाव युद्ध की तरह ही हो गएहैं, जिन्हें जीतने के लिए सच और झूठ, दोनों दांव चले जाते हैं। इसलिए मोदी सरकार को जेपीसी से इस मसले की जांच का फैसला करना चाहिए ताकि इस मुद्दे की धार खत्म हो जाए।

कर्जमाफी का आदेश

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में सरकार गठित होने के साथ ही किसानों की कर्जमाफी का आदेश जारी हो जाने को कई दृष्टियों से देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पदभार ग्रहण करने के साथ सबसे पहला हस्ताक्षर इसी आदेश पर किया। इसका अर्थ है कि चुनाव परिणामों के बाद से ही अधिकारियों ने इस दिशा में काम आरंभ कर दिया था। कांग्रेस दावा कर सकती है कि हमने जो कहा, किया। किंतु क्या यह कदम उतना ही जनकल्याणकारी है, जितना कांग्रेस बता रही है? भारत के ज्यादातर राज्य अपने खर्च और आमदनी में संतुलन नहीं बिठा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इसके अपवाद नहीं हैं। इस अतिरिक्त खर्च को उठा पाना सरकारों के लिए आसान नहीं होगा। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि सरकार इसकी भरपाई के लिए आम जनता से ही परोक्ष रूप से कर वसूलेगी। करों से पूरी नहीं होगी तो खर्च में कटौती करनी होगी। यह कटौती सरकारी महकमे के वेतन और भत्ते में तो नहीं ही हो सकती है। जाहिर है, जनता के लिए होने वाले खर्च में ही कटौती होगी। वैसे भी, किसानों की समस्या का समाधान कर्जमाफी नहीं है। आम किसानों को बैंकों से शायद ही कर्ज मिल पाता है। किसानों की परेशानियां कम करने के लिए खत्म होती परंपरागत आधारभूत संरचना को जितना संभव है, पुनर्जीवित करने तथा उसका विकल्प देने के कदम उठाए जाएं। कर्जमाफी की रकम यदि उसमें खर्च किया जाए तो सच्चे किसानों का ज्यादा भला होगा। वैसे, मध्य प्रदेश सरकार ने वायदे के अनुरूप कर्ज माफ नहीं किया है। सभी किसानों के सारे कर्ज माफ करने की घोषणा की जगह 31 जनवरी, 2018 के 2 लाख तक के कर्ज माफ किए गए हैं। जिन पर दो लाख से एक भी ज्यादा रु पये का कर्ज होगा वह माफी नहीं होगा। इसी तरह खरीफ और नये रबी सीजन के लिए कर्ज लेने वालों का कर्ज भी बना रहेगा। मध्य प्रदेश में किसानों को कर्ज में पहले से ही काफी छूट थी। समय पर जमा करने पर सरकार एक अंश की भरपाई करती थी तथा ब्याज में छूट थी, सो अलग। इसमें यह बहुत बड़ी राहत का कदम नहीं है। हम मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां लोकलुभावन कदमों से बचें, राजनीति करने तथा चुनाव जीतने के लिए ऐसे नारों का इस्तेमाल करें, ऐसे वायदें करें, जिनसे विकास एवं वास्तविक जनकल्याण का रास्ता प्रशस्त हो।

रणनीतियां सफल होना उत्साहित होना स्वाभाविक

कांग्रेस को तीन प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली सफलता के बाद आगे बढ़ने के लिए इन मूल सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। वस्तुत: सफलता के उत्साह में जिस तरह उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और भविष्य की रणनीति का पार्टी जो संकेत दे रही है, उनमें खतरे और जोखिम ज्यादा हैं। दो मामले हमारे सामने हैं-हिंदुत्व विचारधारा और राफेल। राहुल गांधी को हिंदुत्व का चेहरा देने का असर कुछ लोगों पर हुआ है। भारत के मंदिरों से लेकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा ने उनकी और कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि को निस्संदेह कम किया है। किंतु यह तात्कालिक परिणति है। आगे वही लोग यह भी विचार करेंगे कि जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने माना कि भाजपा हिंदुत्व पर कुछ कर रही है, या नहीं, उन पर राहुल और कांग्रेस कितने सक्रिय हैं। अभी कांग्रेस की ओर से खबर दी गई कि राहुल अपनी सांसद निधि से मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएंगे।

सतीश पेडणोकर

रणनीतियां सफल होने पर उत्साहित होना स्वाभाविक है। किंतु उत्साह में अतिरेक हो जाए तो वही रणनीति घातक भी साबित हो सकती है। आवश्यक भी नहीं कि राजनीति में जो रणनीतियां एक समय कुछ स्थानों पर लाभ का कारण बनें, वही दूसरे समय दूसरी जगह या सभी स्थानों पर वैसे ही भूमिका निभाएं। उसकी ऐसी प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं, जो आपको क्षति पहुंचा दें। कांग्रेस को तीन प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली सफलता के बाद आगे बढ़ने के लिए इन मूल सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। वस्तुत: सफलता के उत्साह में जिस तरह उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और भविष्य की रणनीति का पार्टी जो संकेत दे रही है, उनमें खतरे और जोखिम ज्यादा हैं। दो मामले हमारे सामने हैं-हिंदुत्व विचारधारा और राफेल। राहुल गांधी को हिंदुत्व का चेहरा देने का असर कुछ लोगों पर हुआ है। भारत के मंदिरों से लेकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा ने उनकी और कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि को निस्संदेह कम किया है। किंतु यह तात्कालिक परिणति है। आगे वही लोग यह भी विचार करेंगे कि जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने माना कि भाजपा हिंदुत्व पर कुछ कर रही है, या नहीं, उन पर राहुल और कांग्रेस कितने सक्रिय हैं। अभी कांग्रेस की ओर से खबर दी गई कि राहुल अपनी सांसद निधि से मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएंगे। एक टीवी चैनल ने इस पर बहस आरंभ कर दी। मंदिर का जीर्णोद्धार कराने में कोई समस्या नहीं है।

मंदिर हमारी आस्था के केंद्र होने साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक उत्सवों और अनेक आवश्यक निजी कर्मकांडों के केंद्र भी हैं। किंतु इसका प्रचार करने की आवश्यकता क्यों है? यह संदेश देने की कोशिश है कि राहुल का हिंदुत्वनिष्ठ होना केवल दिखावा नहीं है, वे इस दिशा में सक्रिय हैं। आप इस दिशा में कितना करेंगे। धार्मिक नगरों के अनेक पुराने मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिनका उद्धार जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रही है। भाजपा की अन्य प्रदेश सरकारों ने भी किया है। भाजपा के कुछ सांसदों ने भी ऐसा किया होगा तो वे पूरी सूची लेकर सामने आ सकते हैं। एक होड़ शुरू हो जाएगी। धर्म एवं अध्यात्म में आस्था रखने वालों के लिए तो यह अच्छा है। किंतु यह दोधारी तलवार है।

लोग हिंदुत्व के बड़े मुद्दों पर राहुल के स्पष्ट मत एवं सक्रियता की उम्मीद करने लगेंगे जो संभव नहीं हो सकता। उनके लिए यह बोलना कठिन होगा कि अयोध्या में विवादास्पद स्थान पर राममंदिर ही बनेगा। वे चर्च द्वारा हिंदुओं के धर्मांतरण के विरोध में मुखर नहीं हो सकते..मौलवियों के फतवे पर स्पष्ट राय नहीं दे सकते..गोहत्या के विरोध में आक्रामक नहीं हो सकते..। ऐसे अनेक पहलू हैं, जिनमें कांग्रेस की सीमाएं हैं। भाजपा इन पर मुखर और आक्रामक हो सकती है। ऐसा न हो कि राहुल और कांग्रेस के तेवर को देखते हुए नरेन्द्र मोदी और उनके सहयोगी इन मुद्दों पर बचकर मध्यमार्गी छवि बनाने की कोशिश छोड़ पूर्व चरित्र में आ जाएं। ऐसे में राहुल और कांग्रेस के लिए हिंदुत्व पर उनका मुकाबला करना कठिन होगा। इस सीमा तक जाने से अनेक राज्यों में कांग्रेस का अपना वोट ही कट जाएगा। भविष्य के भाजपा विरोधी गठबंधन के कुछ साथियों को भी कांग्रेस के हिंदुत्व पर अतिवादी रवैये से समस्या होगी। उन्हें लगेगा कि मुसलमान वोट कट जाएगा तो वे चुनाव-पूर्व साथ रहने में हिचकेंगे। भाजपा विरोध का जो आधार तथाकथित सेक्युलरवाद है, वो ही इससे खत्म हो जाता है। इस तरह लगातार आगे बढ़ने की सीमाएं और खतरे हैं। संदेश देकर उसी पर काम करते रहना ही कांग्रेस की सही रणनीति होती। राफेल के साथ भी ऐसा ही है। राहुल ने मोदी को चोर कहकर उनकी ईमानदार छवि को धक्का पहुंचाने की कोशिश की। राफेल सौदे पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पहले कांग्रेस पार्टी और बाद में राहुल की प्रतिक्रियाएं तथा दिख रही आक्रामकता का अर्थ यही है कि वे इसे परवान चढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों तथा राहुल के सलाहकारों ने मोदी एवं भाजपा का मुकाबला करने के लिए कुछ रणनीतियां बनाई जिनमें भ्रष्टाचार पर जवाब देने की जगह आक्रामक होना प्रमुख है।

कांग्रेस को 2014 के आम चुनाव या उसके पूर्व के चुनावों में जो क्षति हुई उसका बड़ा कारण यूपीए सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के कलंक थे।कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के समानांतर मोदी की छवि निष्कलंक नेता की थी। इसको तोड़ना था तो कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे उस पर बट्टा लगाया जाए। इस दृष्टि से कांग्रेस और राहुल का राफेल सौदे पर मोदी को घेरना सही लगता है। कारण, रक्षा सौदे इतने संवेदनशील होते हैं कि पूरी जानकारी कोई सरकार सार्वजनिक नहीं कर सकती। आप सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा करते रह सकते हैं। हालांकि इसमें नैतिक प्रश्न अपनी जगह कायम है। बिना आधार आरोप अनैतिक राजनीति के दायरे में आता है। खैर, इसे यहीं छोड़ें। समझें कि 14 दिसम्बर से काग्रेस ने जो रवैया अपनाया है, अब उनके लिए लाभकारी होगा या नहीं? कांग्रेस को लगता है कि पीछे हटते ही 2014 के लिए बनाया आधार कमजोर हो सकता है। किंतु यह खतरा अति तीखापन और आक्रामक बने रहने में भी है। तीन राज्यों में किसी सर्वेक्षण में नहीं आया है कि लोगों ने काग्रेस का साथ इसलिए दिया कि वे मोदी को राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का दोषी मानते हैं। भाजपा राफेल पर जनता को आास्त करने में सफल नहीं रही पर लोगों ने मोदी को चोर मान लिया, इसके भी प्रमाण नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट मत पर कांग्रेस को जरा रु ककर रणनीति बनानी चाहिए थी। लेकिन वे इसे अतिवाद की सीमा तक ले जाने को आतुर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होने के नाते वे कैग एवं महाधिवक्ता को सम्मन करेंगे। विधान इसके आड़े है।

इस बाबत समिति के सदस्यों में ही समर्थन नहीं हैं। ऐसी अतिवादिता के खतरे बहुत हैं। चुनाव में मार खाने के तुरंत बाद आए फैसले से भाजपा ज्यादा आक्रामक हो गई है। हो सकता है राहुल को न्यायालय में भी घसीटा जाए। एक संयमित बयान दे देना ही उचित होता कि न्यायालय के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वस्तुत: हिंदुत्व और राफेल पर जितना चुनावी लाभ मिलना चाहिए उतना मिला है। अतिवाद तक ले जाने से इनकी प्रभाविता खत्म हो जाने तथा इसके प्रतिकूल परिणामों के खतरे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस अज्ञेय की यह पंक्ति याद रखे कि ''कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छुट जाता है'। कौ अंत हौनौ चइऐ!

चलते चलते

''संत जी सत सिरी अकाल

चौरासी में तैंनें बेअंत पै एक कबता लिखी हती, याद ऐ का?-आपको सज्जन कुमार की सजा के बाद बेअंत याद आ रहा है। छोटी सी कविता थी, ''मरकर जब ऊपर पहुंचा बेअंत, तो वहां मिल गए भिण्डरावाले संत। बेअंत ने सिर झुकाया, ''संत जी सत सिरी अकाल।'''सत सिरी अकाल पुतरा, तूने कर दिया कमाल।' कहकर गले लगाया, थपथपाया।''जो काम मैं नहीं कर पाया, बेअंता तूने कर दिखाया। मांग कुछ भी मांग बेटा।' बेअंत साष्टांग लेटा, ''संत जी इन चरणों में थोड़ी-सी जगह दो, मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लो।' संत जी बोले, ''इनाम तो जो चाहेगा दिलवाऊंगा, पर बॉडीगार्ड नहीं बनाऊंगा।' चचा, इंदिराजी चली गई, बॉडीगार्ड बेअंत भी मारा गया। हत्या के बाद गया हत्यारा, लेकिन बेअंत यानी अंतहीन आसानी से

छोटी सी कविता थी, ''मरकर जब ऊपर पहुंचा बेअंत, तो वहां मिल गए भिण्डरावाले संत। बेअंत ने सिर झुकाया, ''संत जी सत सिरी अकाल।' ''सत सिरी अकाल पुतरा, तूने कर दिया कमाल।' कहकर गले लगाया, थपथपाया। ''जो काम मैं नहीं कर पाया, बेअंता तूने कर दिखाया। मांग कुछ भी मांग बेटा।' बेअंत साष्टांग लेटा, ''संत जी इन चरणों में थोड़ी-सी जगह दो,

मरता है कहीं? -का मतलब भयौ तेरी बात कौ?-चौरासी के दंगों में हमने कितने ही सिख पड़ोसियों को लुटते-पिटते और रोते-बिलखते देखा। कॉलोनी के बहुत से गैरसिख भयाक्रांत और मूक दर्शक रहे, तो इक्का-दुक्का ने सिख पड़ोसियों को अपने घरों में छिपाया और बचाया। हमारे घर की दुछत्ती में दो दिन तक टंगे रहे थे सरदार शिवदेव सिंह सेखौं। जब भारत छोड़कर सपरिवार कनाडा गए थे, तो जाते-जाते उन्होंने मुझसे कहा था, ''काके! ऊपर रब ते नीच्चे तूं!' मैं उनके कथन को अपना सबसे बड़ा पुरस्कार मानता हूं। हमारे परिवार का उनके परिवार से निरंतर जुड़ाव बना हुआ है। चचा, धर्म के नाम पर जब भी ध्रुवीकरण होता है, बहुत भारी पड़ता है।-हिंसा बेअंत चौं ऐ हमाए यहां? -क्योंकि नफरतों का अंत नहीं हुआ। जनसमूह-जंगल में जब नफरत की कोई चिंगारी लगती है तो अधकचरे दिमाग बड़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं। बेअंत कहीं पुलिस है, कहीं डाकू है, कहीं नेता है, कहीं संत है, लेकिन उसकी हत्याओं का सिलसिला बेअंत है। ये अंतहीन अभी भी हमारे कानों में फुसफुसा रहा है, खुद तो करता ही है, हत्या के लिए हमें भी उकसा रहा है। अगर हमें सचमुच अपने देश को उद्धारना है, तो सबसे पहले मिलकर अपने अंदर के इस अंतहीन को मारना है।-ऐसे अंतहीन कौ अंत हौनौ चइऐ!

''संतुलित और समावेशी'

राज्यों में हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों से निकला परिणाम यह संकेत दे रहा है कि जनता राजनीतिक स्तर पर मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच विभाजित है और आगामी लोकसभा चुनाव भी इन दो पार्टियों के बीच ही होना संभावित है। अन्य दलों का प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक सीमित है। उनमें से कोई भी दल राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। बसपा की घोषित रूप से गैर-कांग्रेस, गैर-भाजपा की कोई नीति नहीं रही है। उसका उद्देश्य रहा है अपने दम पर सत्ता पर काबिज होना। ऐसी सम्भावना नहीं होने पर वह किसी अभी अन्य पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार नहीं, अपितु बसपा की मदद से बनाने वाली मजबूर सरकार की पक्षधर है। वैसे राजनीति में किसी नीति या सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं होता है। अवसर आने पर, नीति और सिद्धांत तो ताक पर रखकर किसी भी राजनीतिक दल या मोर्चा के साथ तालमेल कर सरकार बनाई जा सकती है। यहां तक कि विरोधी विचारधारा वाले दल या मोर्चा के साथ मिलकर भी। राजनीतिक दलों द्वारा गठबंधन बनाना और तोड़ना आज की राजनीति में सामान्य घटना है। इसका अनुकरण कर बसपा ने भी कई बार सरकार बनाई है। लेकिन बसपा और अन्य पार्टियों में एक मौलिक अंतर है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां किसी-न-किसी रूप में, कम या ज्यादा हिन्दुत्व का पोषण करती हैं और इस रूप में वे वर्ण-व्यवस्था और जातिगत भेदभाव से ग्रस्त भारतीय समाज-व्यवस्था के ताने-बाने को थोड़ी-बहुत लीपापोती के साथ यथावत बनाए रखती हैं। इनमें किसी पार्टी का हिन्दुत्व कट्टर और किसी का उदार हो सकता है। हिन्दुत्व का ही दूसरा नाम ब्राह्मणवाद है। बसपा की पहचान एक अंबेडकरवादी पार्टी के रूप में है और अंबेडकरवाद की दृष्टि में ब्राह्मणवाद दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है। भाजपा के साथ गठजोड़ के दौरान जहां बसपा ने बहुजन से सर्वजनवाद की ओर कदम बढ़ाए, ब्राह्मणवाद ने बसपा की विचारधारा में सेंध लगा दी। आज बसपा न उत्तर प्रदेश में सत्ता में और है और न संसद उसका कोई वजूद है। पिछले कुछ उपचुनावों में उसने भाजपा के विरु द्ध सपा का समर्थन कर अपनी साख बढ़ाने की कोशिश की, किंतु हाल के विधानसभा चुनावों में जिस तरह उसने छत्तीसगढ़ में गैर-भाजपा, गैर-कांग्रेस की नीति को अपनाते हुए अजित जोगी के साथ गठबंधन कर और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अपने दम पर चुनाव लड़ा, उससे लगता नहीं कि कोई बड़ा लाभ उसको हुआ है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भी उसकी स्थिति बहुत सशक्त नहीं है। गैर-कांग्रेस, गैर-भाजपा की नीति अपनाकर अपने बूते चुनाव लड़ना बसपा की राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है। वह भी उन राज्यों में जहां बसपा का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। एक ओर चुनाव बाद कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए समर्थन देना, दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में भाजपा विरोधी मोर्चा की बैठकों से दूर रहना बसपा के द्वंद्व को दर्शाता है। बसपा की यह एक बड़ी कमजोरी रही है कि उसने अपना कोई थिंक टैंक विकसित नहीं किया। बसपा की दूसरी कमजोरी अपने पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना भी रहा है। कई सवालों और सकटों से घिरी बसपा के लिए यह आत्ममंथन का समय है। लोक सभा चुनाव में बहुत अधिक समय नहीं है। बसपा को अभी से यह तय करना होगा कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है और अपनी किस प्रकार की छवि के साथ जनता के बीच जाना है।

सत्संग

''ब्रह्मचारी'

मुझसे कुछ समय पहले पूछा था, ''क्या सिर्फ ब्रह्मचारी ही आप के शिष्य हैं?' मैंने कहा, ''हां, वे ही मेरे शिष्य हैं।' जब मैं कहता हूं,''ब्रह्मचारी', तो इसका मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों से नहीं है, जिन्होंने आधिकारिक रूप से दीक्षा ली है। उनका एक औपचारिक प्रक्रिया से गुजरना कोई मुद्दा नहीं है। हां, कुछ मायने में वे उस मार्ग पर हैं। अगर सवाल है कि क्या सिर्फ ब्रह्मचारी ही मेरे शिष्य हैं? तो मैं कहूंगा कि वे ब्रह्मचारी नहीं हैं तो वे किसी भी तरह से मेरे शिष्य नहीं हैं। उनकी रु चि किसी और चीज में है तो शिष्य होने का सवाल ही कहां है? वे किसी के भी शिष्य नहीं हो सकते। देखिए, आप इनके या उनके शिष्य नहीं होते, यदि आप शिष्य हैं तो हैं, बस यही बात काफी है। आप भक्त हैं तो आप भक्त हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप इन भगवान के भक्त हैं, या उन भगवान के-यह तो बस एक मूर्खता है। आप एक भक्त हैं-यही बहुत है। यह एक गुण है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो (मार्ग दर्शन के लिए) मेरी ओर देखते हैं, लेकिन मुझे गुरू नहीं मानते। वे आगे भी यहां घूमते हुए मिलेंगे। मैं शायद यहां न रहूं। मगर वे यहां घूमते हुए मिलेंगे क्योंकि उन्होंने स्वाद चख लिया है, अब वे खाना चाहेंगे। गुरू का मतलब है, ''अंधकार को मिटाने वाला'। ''गु' का अर्थ है अंधकार और ''रू' का अर्थ है ''मिटाने वाला'। जब आप कहते हैं कि आप के कोई गुरू हैं, तो इसका मतलब आप का अंधकार मिट गया है। तब आप यहां फिर से क्यों होंगे? आप का अंधकार दूर होने या मिटने का मतलब यह नहीं है कि आप प्रकाश हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप ''कुछ नहीं' हो गए हैं, आप खुद अंधकार बन गए हैं। फिर कुछ दूर करने की जरूरत ही नहीं रहती। अगर आप इससे दूर हैं, तो अंधकार एक भयानक बात है। अगर आप अंधकार बन जाते हैं, तो यह अनंत या असीम होना है। अंधकार भयानक इसलिए है क्योंकि आप किसी चीज के एक छोटे से हिस्से की तरह हैं। आप अंधकार हो जाते हैं, तो फिर कोई सीमा नहीं रहती। मैं आप को आशीर्वाद दूं कि ''आप अनंत हो जाएं' तो आप को अच्छा लगेगा पर अगर मैं आप को आशीर्वाद यह दूं कि ''आप अंधकार बन जाएं', तो आप को यह श्राप जैसा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अंधकार अनंत है, अनंत होना ही अंधकार है।

फोटोग्राफी...

दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के को एक्स एक्युरियम में रुडोल्फ कॉस्ट्यूम और सांता क्लॉज की ड्रेस में परफॉर्म करते गोताखोर।

सार समाचार

युगांडा बस दुर्घटना में 19 एनजीओ कार्यकर्ताओं की मौत पुलिस

कंपाला। पूर्वी युगांडा में हुए बस हादसे में एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के कम से कम 19 कर्मियों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बस के अनियंत्रित होकर एक ऊंची चट्टान से लुढ़क जाने के कारण यह हादसा हुआ। क्षेत्रीय पुलिस के प्रवक्ता रोगर्स तैतिका ने मंगलवार को बताया कि बस चट्टान से लुढ़कती हुई दर्रे में जा गिरी और इसमें 19 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है तथा छह अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह बस अमेरिका के एक एनजीओ के स्टाफ को उनकी वार्षिक पार्टी के लिए कापचोरवा ले जा रही थी। कंपाला से 300 किलोमीटर पूर्व में स्थित सिपी के पास यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तैतिका ने कहा, ऽहम हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं। मृतकों की पहचान किरयनडोंगो और मासिंदी जिलों (दक्षिणी युगांडा) में काम करने वाले एनजीओ के कर्मियों के रूप में हुई है। संगठन और मृतकों के बारे में अन्य विवरण तत्काल नहीं मिल सका। सड़क सुरक्षा के मामले में युगांडा का रिकॉर्ड बेहद खराब है। वाहनों एवं सड़कों की खराब स्थिति के साथ ही खतरनाक ड्राइविंग भी हादसों के लिए जिम्मेदार है।

ट्रंप ने फेसबुक, ट्विटर, गूगल पर लगाया पक्षपात का आरोप

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियों को मंगलवार को निशाने पर लिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ये कंपनियां विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट के समर्थन में पक्षपात करती हैं।
ट्रंप ने ट्वीट किया, ''फेसबुक, ट्विटर और गूगल डेमोक्रेट्स के प्रति इतना झुकाव रखती हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तव में ट्विटर ने तो लोगों के लिए मेरे ट्विटर हैंडल से जुड़ना बेहद कठिन बना दिया है।'' ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कई नाम हटा दिये हैं और इसमें वृद्धि की गति तथा स्तर को नीचे कर दिया है।

सिख ड्राइवर पर जान लेवा हमला करने वाले अमेरिकी को 15 माह की जेल

न्यूयॉर्क, प्रेट्र। पिछले साल सिएटल में 53 साल के एक सिख टैक्सी ड्राइवर पर हथौड़े से हमला करने वाले अमेरिकी को यहां की एक अदालत ने 15 महीने जेल की सजा सुनाई है। अमेरिका में सिखों के अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था द सिख कोएलिशन के अनुसार, दिसंबर 2017 में रोरी बेंसन ने सिख ड्राइवर स्वर्ण सिंह पर बेरहमी से वार किया था। बेंसन को बीते शुक्रवार को अदालत ने दोषी करार दिया था।
स्वर्ण सिंह पर यह हमला उस वक्त किया गया था जब उन्होंने बेंसन और उसकी मां को छोड़ने के लिए एक अपार्टमेंट के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी की थी। बेंसन ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठा था। बेंसन ने गाड़ी साफ करने के लिए रखे गए कपड़े से सिंह का मुंह दबाने की कोशिश की। सिंह किसी तरह गाड़ी से बाहर निकले तो बेंसन ने अपने बैग से हथौड़ा निकाल कर उनका पीछा किया। उसने सिंह के सिर पर कई वार किए थे। इस हमले में सिंह को गंभीर चोटें आई थीं। घटना के तुरंत बाद बेंसन को गिरफ्तार कर लिया गया था।

एच-4 वीजा से जुड़े एक मुकदमे को अमेरिकी अदालत ने लंबित श्रेणी से हटाया

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका की एक अदालत ने एच-4 वीजा के तहत एच1-बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को मिलने वाले काम के अधिकार को चुनौती देने वाले एक मुकदमे को 'लंबित रखने' की श्रेणी से हटा दिया है. इस पर अब सुनवाई किए जाने की संभावना है. अदालत के नए आदेश के मुताबिक इस मुद्दे को उठाने वाला समूह 'सेव जॉब्स यूएसए' 16 जनवरी 2019 तक अदालत में नयी जानकारियां दे सकता है. वहीं ट्रंप सरकार के पास अपना जवाब दाखिल करने के लिए 22 फरवरी 2019 तक का समय है.

इसके अलावा अदालत ने इस मामले में 'इमिग्रेशन वॉइस' को भी हस्तक्षेप करने अर्थात वादी बनने की अनुमति दे दी है. इमिग्रेशन वॉइस एक गैर-लाभकारी संगठन है जो अमेरिका में उच्च कौशल योग्यता वाले कर्मचारियों की समस्याओं के लिए काम करता है.

उल्लेखनीय है कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार, एच1-बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को काम का अधिकार देने वाले एच-4 वीजा से जुड़े नियमों में संशोधन करना चाहती है और इसे लेकर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने वाली है, लेकिन इस अधिसूचना के जारी होने में देरी के चलते इससे जुड़े एक मुकदमे को अब अमेरिका की अदालत ने 'लंबित श्रेणी' से हटा दिया है.

एच1-बी वीजा विदेशी लोगों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है और उनके जीवनसाथियों को एच-4 वीजा जारी किया जाता है. ट्रंप की पूर्ववर्ती बराक ओबामा सरकार ने 2014 में एच-4 वीजा के माध्यम से एच1-बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को भी अमेरिका में काम करने का अधिकार प्रदान किया था. इस कानून में संशोधन से यहां काम करने वाले बहुत से भारतीय प्रभावित होंगे.

ओबामा सरकार के फैसले को अमेरिका की एक स्थानीय अदालत ने बरकरार रखा था जिसके बाद 'सेव जॉब्स यूएसए' नाम का एक समूह इस मामले को अपीलीय अदालत ले गया था. लेकिन अदालत ने इस मामले को लंबित कर दिया था क्योंकि ट्रंप सरकार ने अदालत को तीन बार सूचित किया कि वह ओबामा प्रशासन के दौरान लिये गये इस फैसले को वापस लेगी और जल्द ही इस बारे में आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी.

सितंबर में 'सेव जॉब्स यूएसए' ने अदालत से इस प्रकरण को लंबित मुकदमे की श्रेणी से हटाने और इस पर आगे कार्रवाई करने का अनुरोध किया. कोलंबिया डिस्ट्रिक की अमेरिकी अपीलीय अदालत ने 17 दिसंबर को अपने आदेश में इस मामले को लंबित श्रेणी से हटा दिया और इस पर मौखिक सुनवाई करने की मंजूरी प्रदान कर दी. अब यह मामला तीन सदस्यों वाली पीठ के समक्ष है और इसमें एक न्यायाधीश भारतीय मूल के अमेरिकी श्री श्रीनिवासन भी शामिल हैं.

कांगो में प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति जोसेफ के पार्टी मुख्यालय में तोड़फोड़

शिकापा। कांगो के राष्ट्रपति जोसेफ कबीला का समर्थन करने वाले एक उम्मीदवार के यहां पहुंचने पर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई। देश में 23 दिसंबर को चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति कबीला 17 साल से सत्तारूढ़ हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के

मुताबिक अशांत मध्य कसई क्षेत्र के शहर शिकापा में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कबीला के पार्टी मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई जिसका पूरा विवरण अभी नहीं मिला है।

एक स्थानीय एनजीओ के मुताबिक सैनिकों ने प्रदर्शन कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाईं और एक महिला दुकानदार के सिर में गोली मार दी। स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। रविवार को होने वाले चुनावों से पहले यहां काफी तनाव देखने को मिल रहा है। इस हिंसा से पहले पिछले हफ्ते के अंत में हुई झड़पों में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 80 लोग घायल हो गए थे। कबीला के करीबी सहयोगी एवं उनका समर्थन करने वाले उम्मीदवार एमैनुएल शादरी का चुनाव प्रचार हिंसा के चलते रद्द हो गया।

कांगो: प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति कबीला के पार्टी मुख्यालय में 'तोड़फोड़', एक की मौत

शिकापा (एजेंसी)।

कांगो के राष्ट्रपति जोसेफ कबीला का समर्थन करने वाले एक उम्मीदवार के यहां पहुंचने पर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन हुआ. इस दौरान एक महिला की मौत हो गई. देश में 23 दिसंबर को चुनाव होने हैं. राष्ट्रपति कबीला 17 साल से सत्तारूढ़ हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अशांत मध्य कसई क्षेत्र के शहर शिकापा में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कबीला के पार्टी मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई.

इस दौरान एक महिला की मौत हो गई जिसका पूरा विवरण अभी नहीं मिला है. एक स्थानीय एनजीओ के मुताबिक सैनिकों ने प्रदर्शन कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाईं और एक महिला दुकानदार के सिर में गोली मार दी.

स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है.

रविवार को होने वाले चुनावों से पहले यहां काफी तनाव देखने को मिल रहा है. इस हिंसा से पहले पिछले हफ्ते के अंत में हुई झड़पों में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 80 लोग घायल हो गए थे. कबीला के करीबी सहयोगी एवं उनका समर्थन करने वाले उम्मीदवार एमैनुएल शादरी का चुनाव प्रचार हिंसा के चलते रद्द हो गया.

विश्व आर्थिक मंच की बैठक के लिए दावोस जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में भाग लेने दावोस जाएंगे। यह लगातार दूसरा साल होगा जब ट्रंप इस बैठक में शामिल होंगे।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने बताया, ''आप जानते हैं कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक 22 से 25 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में होगी। राष्ट्रपति पिछले साल की तरह इस साल भी इसमें शिरकत करेंगे।'' हालांकि ट्रंप ने 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि बनने के भारत के अनुरोध को ठुकरा दिया है।

चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच पोम्पिओ ने नेपाल के विदेश मंत्री से की मुलाकात

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के मद्देनजर हिमालयी देश के विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली के साथ एक दुर्लभ बैठक की। पोम्पिओ ने मंगलवार को ज्ञवाली के साथ हुई बैठक को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि यह कदम नेपाल के साथ साझेदारी मजबूत करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप-प्रवक्ता रॉबर्ट पालाडिनो ने कहा कि पोम्पिओ ने अमेरिका-नेपाल के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान पोम्पिओ ने अमेरिका-नेपाल भागीदारी की स्थायी ताकत और लोगों के आपसी मेलजोल को रेखांकित किया। पालाडिनो ने कहा, ''दोनों नेताओं ने नेपाल के 50 करोड़ डॉलर के 'मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन कॉम्पैक्ट', उत्तर कोरिया सहित एक मुक्त, खुले और समृद्ध हिंद-प्रशांत और वैश्विक मुद्दों पर नेपाल की प्रमुख भूमिका को लेकर चर्चा की।''

बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने की इस्तीफे की घोषणा

बुडापेस्ट (एजेंसी)।

ब्रसेल्स। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने इस्तीफे की घोषणा की है। लगभग दो सप्ताह पहले आव्रजन के मुद्दे पर उनके मुख्य गठबंधन सहयोगी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था जिससे उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। वर्ष 2014 में पद संभालने वाले मिशेल ने संयुक्त राष्ट्र आव्रजन समझौते पर अपने समर्थन के चलते न्यू फ्लेमिश अलायंस (एन- वी ए) का समर्थन खो दिया। मंगलवार को उनका इस्तीफा तब आया जब दो दिन पहले

मध्य ब्रसेल्स में समझौते के विरोध में हुए प्रदर्शन संघर्ष में बदल गए और पुलिस को आंसू गैस के गोले तथा पानी की बौछारें छोड़नी पड़ीं। संसद में चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने उनकी सरकार को मई में होने वाले चुनाव तक बनाए रखने के लिए अपना समर्थन जारी रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद मिशेल ने इस्तीफा देने की घोषणा की। सांसदों द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से पहले मिशेल ने कहा, ''मैंने इस्तीफा देने का निर्णय किया है और मैं तत्काल राजा से मिलना चाहता हूं।'' राजमहल ने एक बयान में कहा कि राजा फिलिप ने मिशेल का इस्तीफा स्वीकार करने से पहले विचार-विमर्श करने का फैसला किया है। देश के कृषि मंत्री एवं मिशेल की पार्टी मूवमेंट रिफॉर्मेटर के नेता डेनिस डुकार्ने ने देश को संकट में डालने का खतरा उठाने के लिए वामपंथी और ग्रीन पार्टियों की निन्दा की।

मां की ममता के आगे ट्रंप भी गए हार, मरने से पहले बेटे को आखिरी बार चूमने की चाहत होगी पूरी

सना (एजेंसी)।

आखिरकार एक मां की ममता के आगे ट्रंप प्रशासन को झुकना पड़ा और अपने बेटे को आखिरी बार चूमने की हसरत संजोये इस मां की जिद ने ट्रंप प्रशासन को यमन पर लगाये गये यात्रा प्रतिबंध में रियायत देने पर मजबूर कर दिया. यमनी महिला अल शायमा स्विलेह अपने बेटे की मौत से पहले उसे आखिरी बार चूमना चाहती थीं. उनकी यह ख्वाहिश अब पूरी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने लंबी लड़ाई के बाद ट्रंप प्रशासन से यात्रा में रियायत की इजाजत ले ली है. इसलिए अब वह कैलिफोर्निया जाकर अपने दो साल के मासूम बेटे से मिल सकेंगी.

शायमा का बेटा जीवन रक्षक प्रणाली पर है. रियायत पाने के लिये परिवार ने करीब एक बरस तक कानूनी लड़ाई लड़ी. पिछले सप्ताह काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस के वकीलों के मुकदमे के बाद आखिरकार अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को स्विलेह को यह छूट दे दी.

स्विलेह का बेटा अब्दुल्ला ऑकलैंड में यूसीएसएफ बेनिऑफ चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल में भर्ती है जिसे देखने के लिये वह बुधवार को सैन फ्रांसिस्कों के लिये उड़ान भरने की योजना बना रही हैं. काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस के सैक्रामेंटो खंड द्वारा उपलब्ध बच्चे के पिता अली हसन के बयान के अनुसार, ''इससे अब हम इज्जत से मातम कर सकेंगे.''

हसन अमेरिकी नागरिक हैं और वह स्टॉकटॉन में रहते हैं. हसन, मस्तिष्क संबंधी अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे अपने बेटे को बेहतर उपचार के लिये कैलिफोर्निया लेकर आये थे. वीजा की अनुमति मिलने से एक दिन पहले सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए हसन ने सार्वजनिक अपील की.

पत्रकारों के सामने वह फूट-फूट कर रो पड़े, उन्होंने कहा, ''मेरी बीवी मुझे रोज फोन करती है. वह अपने बेटे को चूमना चाहती है और बेटे के आखिरी वक्त में उसे अपने सीने से लगाना चाहती है.'' युद्धग्रस्त यमन में 2016 में शादी के बाद यह दंपति मिस्र आ गया. हसन 2017 से ही स्विलेह के लिये वीजा की कोशिश कर रहे थे ताकि दोनों कैलिफोर्निया आकर रह सके.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू यात्रा प्रतिबंध के तहत उत्तर कोरिया एवं वेनेजुएला सहित यमन एवं चार अन्य मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध है. हसन ने सैक्रामेंटो बी अखबार के साथ साक्षात्कार में कहा, ''मैं उन्हें ईमेल करता, रोता और बताता कि मेरा बेटा मर रहा है.''

उन्होंने कहा, मैं नाउम्मीद हो गया था और बेटे को पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने उसे जीवन रक्षक प्रणाली से हटवाने की सोच ली थी. तभी अस्पताल में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने काउंसिल से संपर्क किया. सैक्रामेंटो में काउंसिल के बासिम एल्कारा ने बताया कि स्विलेह महीनों अपने बच्चे से दूर रहीं. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता रॉबर्ट पालाडिनो ने इसे ''बेहद दुखद मामला'' बताया और कहा कि दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं.

पाक बातचीत के जरिए कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण हल चाहता है: कुरैशी

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को कहा कि उनका मुल्क कश्मीर मुद्दे का ''टिकाऊ और बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण'' समाधान चाहता है। सेना की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, कुरैशी ने यह टिप्पणी इस्लामाबाद में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी (एनडीयू) में राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध पाठ्यक्रम में शिरकत रहे लोगों को संबोधित करते हुए की। पाकिस्तान की विदेशी नीति की बुनियाद, चुनौतियों और मौकों को रेखांकित करते हुए कुरैशी ने कहा, '' देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को महफूज रखते हुए हम हमला रोकने के लिए विश्वसनीय राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को बनाए रख रहे हैं।'' विदेश मंत्री ने कहा, ''पाकिस्तान कश्मीर विवाद का टिकाऊ और बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान चाहता है।''

आपको बता दे कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और बिना उकसावे के अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे एलओसी पर पाकिस्तानी जवानों की ओर से की गई गोलीबारी का भारतीय जवानों ने कड़ा और प्रभावी जवाब दिया। अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने के बारे में तत्काल कोई खबर नहीं मिली है। इससे ये साफ होता है कि पकिस्तान की कथनी और करनी में कितना फर्क है करतारपुर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते है पकिस्तान तो दुसरी तरफ पीठ पर छूरा भौंकता है सरहद पर हमारे देश के जवानों को मार कर।

सिर्फ ट्यूशन क्लासेज पर ही कार्रवाई क्यों ?

नियमों को ताक पर रखने वाले स्कूलों के खिलाफ क्यों नहीं

सूरत। वेसू के आगम आर्केड में लगी आग की घटना में ट्यूशन क्लासेस के विद्यार्थी की हुई मौत के बाद भले ही सूरत महानगर पालिका का फायर एण्ड सेफ्टी विभाग एक्टिव मोड में नजर आ गया है परन्तु विभाग की यह सक्रीयता नाकाफी साबित हो रही है। फायर विभाग के अधिकारी मात्र ट्यूशन क्लासेज को ही टार्गेट कर अपनी खानापूर्ति कर रहे है तथा कार्रवाई के नाम पर छोटे-मोटे ट्यूशन संचालों को आतंकित कर अपना लक्ष्य पूरा कर रहे है। जबकि शहर में चल रहे ह जारों की संख्या में नीजी स्कूलों में फायर एण्ड सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। इन नीजी स्कुलों में न तो फायर फायटिंग सिस्टम लगे है और न ही अपातकाल की स्थिति में सुरक्षित बचक निकलने की वैकल्पिक व्यवस्था है। इन स्कूलों में दिन में दो पालियों में बच्चों को पढाया जाता है। जिनसे फीस के नाम पर मोटी रकम वसूल की जाती है।

धडल्ले से सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाने वाले इन स्कूलों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई न किया जाना इस बात की तरफ संकेत करता है कि फायर सेफ्टी विभाग सिर्फ उनकों ही टार्गेट चला रहे है जो किसी तरह अपनी रोजी रोटी चला रहे है। शहर के अन्दर ऐसे सैकड़ों स्कूल है जिनके पास न खेल के मैदान है और ना ही बच्चों के लिए व्यवस्थित शौचालय है। इन स्कूलों में जो शौचालय है वे इतनी गंदी अवस्था में है कि स्वास्थ बच्चे भी बीमार हो रहे है। जब तक फायर एण्ड सेफ्टी विभाग इन स्कूलों पर कार्रवाई नहीं करता तब तक उसकी इस कार्रवाई को बेमानी ही कहा जा सकता है। ऐसे में शहर के नागरिकों की दृष्टी में अपने को पाक साबित करने के लिए विभाग को स्कूलों के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए।

सूरत महानगर पालिका का फायर विभाग यदि इन स्कूलों का भी सर्वे कर कार्रवाई करे तो ही सही मायने में विभाग का कार्य सराहनना के योग्य माना जाएगा।

आंजना कचरा डिस्पोजल साईट पर चल रहे स्कूलों में विद्यार्थियों की हालत खराब

सूरत। शहर के आंजना क्षेत्र संचालित रामप्रसाद विस्मिल शाला के लगभग 1200 विद्यार्थियों का कचरे की दुर्गंध से हालत खराब है। यहां पर चल रहे बायो गैस प्लांट तथा कचरे की बदबू के बीच बच्चे यहां पढने के लिए मजबूर है। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा टी. पी. नं.-7 आंजना, फाईनल प्लाट नं. 98 में संचालित रामप्रसाद विस्मिल शाला क्रमांक 198,252 तथा 186 उर्दू माध्यम की शाला में पढ़ रहे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य खतरे में नजर आ रहा है।

वसूली के 5.5 लाख पचाने के लिए गढी लूट की कहानी

सूरत। उधना के खरवर नगर के निकट लूट की घटना की जानकारी मिलते ही उधना के पी.आई. एम.एफ पठान पी.एस.आई. वी.एच. वाणांद फौरन मौके पर पहुंच गए। लूट की वारदात में घाल व्यक्ति से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने लूट की घटना को नाटक स्वीकार कर लिया। पुलिस ने इस नाटक में शामिल 4 लोगों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार साड़ी के बाक्स प्रिंटिंग के व्सवसाय से जुड़े मुकेश धनराज जैन के प्रिंटिग प्रेस में काम कनरे वाला अविनाश अशोक जैन 18 दिसंबर को उधना खरवर नगर के पास से गुजर रहा था तभी कुछ लूटेरों ने उसके पास से वसूली के 5.5 लाख रुपये लूट लिया। घटना की जानकारी मिलेत ही पुलिस एर्लट मोड मे आ गई। लूट की घटना में घायल हुए अशोक जैन का स्मीमेर हास्पीटल में उपचार करा रहा था। पुलिस ने जब स्मीमेर हास्पीटल पहुंचकर अशोक से घटना के संदर्भ में पुछताछ की तो अशोक ने लूटकी घटना को नाटक स्वीकार कर लिया। पुछताछ में अशोक ने बताया की उसने अपने मित्र मुन्ना, समीर, तथा शैलेष के साथ मिलकर लूट का नाटक रचा था। ताकी प्रिंटिंग के रुपयों की वसूली के 5.5 लाख रुपये हजम कर सके।

समग्र दक्षिण गुजरात में ठेड का प्रभाव, सूरत में 12 डीग्री पर पहुंचा पारा

सुरत। उत्तर भारत में चल रही बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर की तरफ से चलने वाली हवाओं के चलते समग्र दक्षिण गुजरात में ठंड का प्रभाव बढ़ गया है। बुधवार को सूरत का न्यूनतम तापमान 12 डीग्री दर्ज किया गया। हाड़ कपकपाती ठंड के कारण लोग देर तक घरों मे दुबके रहे। बुधवार को नवासीर में 9 डीग्री वलसाड में 11 डीग्री तथा सूरत में 12 डीग्री तापमान रहा। सूरत मौसम विभाग से मिली जानकारी अनुसार बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.8 डीग्री तथा न्यूनतम तापमान 12 डीग्री रहा। हवा में नमी की मात्रा 58 प्रतिशत तथा हवा का दबाव 1080 मिलीबार दर्ज किया गया। शहर में उत्तर पूर्व की दिशा से 5 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से दिनभर हवाएं चली। मंगलवार की तुलना में बुधवार को तापमान में 2 डीग्री की गिरावट देखने को मिली। नवसारी मौसम विभाग से मिली जानकारी अनुसार बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान तथा न्यूनतम तापमान में 2.5 डीग्री की गिरावट देखी गई। बुधवार को नवसारी का न्यूनतम तापमान 9 डीग्री तथा वलसाड़ का 11 डीग्री दर्ज किया गया।

कारखानेदार से जाब वर्क कराकर 1.72 लाख की ठगी

महेशभाई तातिया के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायत

सूरत। कारखानेदार के पास से 1.72 लाख रुपये का जार्ब वर्क कराकर भुगतान न करने वाले व्यापारी के विरुद्ध पुलिस ने शिकायर्त दर्ज कराई गई है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार मूल जूनागढ के विसावदर तालुका के मोटी मोडपरी गांव निवासी तथा वर्तमान में पासोदरा के शिवशक्ति सोसायटी में रहने वाले उमेश भाई नानजीभाई गोडलिया एम्ब्रोईडरी का कारखाना चलाते है। उमेश भाई पिछले 7 वर्षों से तातिया ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक महेशभाई बजरंगदास तातिया के साथ एम्ब्राइडरी का काम कर रहे थे। महेश तातिया ने इस दौरान उमेश को भरोसे में लेकर उधार मे जाब वर्क कराना शुरु कर दिया। जिसे बाद में चुकाने से मना कर उमेशभाई के साथ विश्वास घात किया है। महेश की तरफ से निकलने वाले 1.72 लाख रुपये न चुकाने की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

किरण ज्वैल्र्स सोना चोरी मामले में 5 संदिग्धों की दरपकड़

सूरत। सूरत शहर की प्रसिद्ध डायमंड पेढी किरण ज्वैल्र्स के कतारगाम यूनिट में हुई 1.21 कोरड़ के सोने की चोरी मामले में पुलिस ने 5 संदिग्धों की धरपकड़ की है। डायमंड मेंशन बिल्डिंग की कंपाउंड में दीवाल फांदकर घुसे चोरों ने एक्जास्ट फैन तथा खिड़की का ग्रील तोड़कर ज्वैलरी बनाने के लिए गलाए गए 3 किलो 8 36 ग्राम वजनी शुद्ध सोने का पावडर चुरा ले गए। करोड़ों के सोने की चोरी की इस घटना से पुलिस विभाग में हडकंप मच गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियो की धरपकड़ की है। पुलिस की जांच मे पता चला है कि चोरी का मुख्य आरोपी पहले यहीं नौकरी करता था। जिसने यहां काम करते समय ही चोरी का प्लान बनाया होगा। विदित हो कि डायमंड बुर्स के चेयरमैन तथा भावनगर जिला के वल्लभीपुरा तालुका के भोजपुर गांव के मुख्य निवासी वल्लभभाई लखानी की किरण ज्वैलर्स नाम की ज्वैलरी यूनिट नंदू दोशी की वाड़ी के पास डायमंड मेंशन बिल्डिंग मे चलता है। इस यूनिट में वरुण बाबूभाई वाघाणी तथा मेहुलभाई वाधाणी पार्टनर है। कंपनी में तैयार होने वाले डायमंड तथा गोल्ड की ज्वैलरी में से कीमत से अधिक का सोना तथा हीरा का स्क्रेप इक्कट्ठा कर उसे प्रेसेस कर लिक्विड बनाया जाता था। जिसे बाद में पावडर के फार्म में बनाकर उसमें से शुद्ध सोना अलग किया जाता था। सोमवार की रात इसी जगह से करोड़ों के सोने की चोरी हुई थी। जिसके बाद कतारगाम पुलिस के अलावा पुलिस के

आला अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। इस मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 5 संदिग्धों की धरपकड़ की है। जिनसे पुछ ताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही चोरी की घटना में शामिल आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा तथा चुराए गए सोने को बरामद कर लिया जाएगा। पुलिस इस मामले में डाग स्क्वायड तथा एप.एस.एल की मदद ले रही है। घटना के संदर्भ में कंपनी के मैनेजर सचिन दिनकभाई भामरे ने कतारगाम पुलिस में 1 करोड़ 20 लाख रुपये कीमत के सोने की चोरी की शिकायत दर्ज कराई है।

बेल्जियम स्क्वेयर में संचालित फिनोमिनल हेल्थ केयर कंपनी फरार

सूरत। शहर के रेल्वे स्टेशन क्षेत्र स्थित बेल्जियम स्क्वेयर के दूसरी मंजिल पर फिनोमिनल हेल्थकेयर के नाम से संचालित इन्वेस्टमेंट कम्पनी के अचानक फरार हो जाने से निवेशकों में अफरा तफरी मच गई। कंपनी के संचालकों के एजेंटों तथा निवेशकों को तुभावनी लालच देकर 6 करोड़ से अधिक की ठगी की शिकायत महिधरपुरा पुलिस में दर्ज कराई गई है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार सचिन के सी.आर. पाटील नगर स्थित लक्ष्मीवाला टाउनशिप में रहने वाले रामनयन रामतीर्थ पांडेय ने मंगलवार को महिधरपुरा पुलिस में फिनोमिनल हेल्थ केयर कंपनी के सूरत तथा मुंबई के चेयरमैन डायरेक्टर तथा एम.डी के विरुद्ध 6 करोड़ की ठगी तथा विश्वासघात की शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस को दिए शिकायत में कंपनी के चेयरमैन लंदलाल, वाईस चेयरमैन टी.एम.एस नायर, एम.डी.एम.के सिंह गुजरात जोन डायरेक्टर रामसजीवन शुक्ला अमरनाथ तिवारी, प्रभाकर मिश्रा को आरोपी बनाते हुए कहा है कि इन लोगों ने सांठ गाठ कर लोगों को ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपये अपनी कंपनी के खाते में जमाकर लिया। जब रुपये लौटाने की बारी आई तो ये सभी आफिस बंद करके फरार हो गए। गौरतलब है कि सूरत सहित देश भर में ऐसी बहुत सारी चीटफंड कंपनियां चल रही है जो अक्सर ज्यादा ब्याज का लालच देकर लोगों के मेहनत की गाढी कमाई अपने पास जमा कर लेते है और मौका मिलते ही यह रकम लेकर फरार हो जाते है। बाद में ठगी के शिकार बने लोगों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है। जब तक आरोपीयों के उपर कार्रवाई की जाती है तब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से काफी दूर जा चुके होते है।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि यदि समय रहते इस तरह की कम्पनीयिों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है।

बस तथा पिकअप वैन में जोरदार टक्कर

पीकअप में सवार दो बच्चों की मौत 16 घायल

सूरत। बुधवार की सुबह व्यारा मंडवी रोड़ पर काकरापारा अणुमाला एटामिक प्लांट की बस द्वारा मजदूरों से भारी पीकअप वैन में पीछे से टक्कर मारने से हुई भीषण दुर्घटना में 2 बच्चों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि वैन में सवार 16 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। काकरापार पुलिस से मिली जानकारी अनुसार बुधवार की सुबह 7.30 बजे के करीब व्यारा-मांडवी रोड़ स्थित उचामाला गांव के निकट हुई वाहन दुर्घटना में दो बच्चों की मैके पर ही मौत हो गई जबकि वैन में सवार अन्य 16 लोगों को चोटे आई।

कारण बताए बगैर ट्रांजेक्शन रोकने पर एसबीआई को 25 हजार का जुर्माना

सूरत। वरिष्ठ नागरिक का बिना कारण बताए बगैर ट्रांजेक्शन रोकने पर कंजुमर कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को रु. 25000 का जुर्माना किया है। जानकारी के मुताबिक 67 वर्षीय जयंतिलाल ठक्कर का अडालज स्थित एसबीआई में बचत खाता है। मई 2014 में बैंक ने रु. 17000 का ट्रांजेक्शन नहीं किया था। वृद्ध ने जब ट्रांजेक्शन नहीं करने के बारे में पूछा तो बैंक से जवाब मिला ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेशन में गड़बड़ी के कारण ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया। इसके लिए बैंक अधिकारी ने जयंतिलाल से माफी मांग ली। लेकिन जुलाई महीने में फिर वही गलती दोहराई गई और जयंतिलाल अपने खाते से रु. 7000 नहीं निकाल पाए। बैंक ने जयंतिलाल को बताया कि 2014 में उन्होंने दिया चेक पास नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्हें पैनल्टी देनी पड़ी। खाते में बेलैंस कम होने के कारण जयंतिलाल को रु. 1495 की पैनल्टी भी लगी। बैंक सेवा से नाराज जयंतिलाल ठक्कर ने गांधीनगर जिला कंजुमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में एसबीआई के खिलाफ शिकायत कर दी, जिसके आधार पर एसबीआई को नोटिस जारी की गई। लेकिन बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर एकतरफा सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता बैंक सेवा से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बैंक निवृत्त नागरिक का खाता ब्लॉक कर उसे परेशान कर रही है, जिसके एसबीआई को मुआवजा देना होगा। कंजुमर कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया है कि वह रु. जयंतिलाल को रु. 25000 का मुआवजा दे। साथ ही हर्जा-खर्चा के लिए अतिरिक्त रु. 4000 तथा खाते में पर्याप्त बेलैंस नहीं होने पर बतौर पैनल्टी लिए गए 1495 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के जयंतिलाल को देने का कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया है।

21 दिसंबर को सुबह 11 बजे के बाद स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आने का अनुरोध

सूरत। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं अन्य महानुभाव आगामी 21 दिसंबर को केवड़िया स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के दौरे पर आएंगे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के प्रशासनिक अधिकारी ने आगंतुकों से शुक्रवार, 21 दिसंबर के दिन सुबह 11.00 बजे के बाद स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने का अनुरोध किया है। शुक्रवार को ही शाम का प्रोजेक्शन मैपिंग और लाइट एंड साउंड शो भी पर्यटकों के लिए बंद रहेगा।

अहमदाबाद-पोरबंदर के बीच विमान सेवा शुरू

सूरत। अहमदाबाद और पोरबंदर के बीच आज से विमान सेवा का प्रारंभ हो गया। टू जेट की ओर से प्रारंभ की गई यह सेवा रविवार को छोड़ सभी दिवसों में उपलब्ध होगी।

35 यात्रियों की क्षमता वाले इस लाइट का किराया रु. 1200 से रु. 2000 तक होगा। अहमदाबाद-पोरबंदर के बीच लाइट सुबह 7.15 बजे अहमदाबाद से रवाना होगी और 8.35 बजे पोरबंदर पहुंचेगी। पोरबंदर से यह लाइट 8.55 बजे रवाना होकर 10.15 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। अहमदाबाद-पोरबंदर के अलावा टू जेट अहमदाबाद जैसलमेर के बीच विमान सेवा का आज से प्रारंभ किया है।

उधना जलाराम वे ब्रिज पर जी.एस.टी का छापा

सूरत। जीएसटी लागू होने के डेढ साल बीत जाने के बाद अब सेंट्रल गुडस एण्ड सर्विस टेक्स विभाग द्वारा असरदार कार्रवाई शुरु हुई है। बुधवार की सुबह जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने उधना स्थित जलाराम वे ब्रिज के कार्यालय पर छापेमार कर जांच पड़ताल की गई। जिसमें अनियमितता पाये जाने पर अधिकारियों ने कार्यालय को सील कर दिया।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी विभाग द्वारा कुछ समय पहले कहा गया था कि आने वाले समय में जीएसटी को लेकर हेरा फेरी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विभाग की इस कार्रवाई से पहले से ही मंदी की मार झेल रहे टेक्सटाईल व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। विदित हो की जीएसटी नें. लेकर कुछ व्यापीर सिर्फ सेल-परचेज का बिल कागजों पर बनाकर सरकार को चुना लगा रहे थे। जिन पर अधिकारियों की जनर पहले से ही थी। परन्तु पिछले डेढ वर्षो में किसी तरह की कार्रवाई न होने से हेरा फेरी करने वाले निश्चित हो गए थे। उधना में हुई इस कार्रवाई से व्यवसायियों में भय का वातावरण बना हुआ है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)